ईवी के साथ दूसरे विकल्पों पर देना होगा ध्यान : संजीव

ईवी के साथ हाइब्रिड और फ्लेक्सी फ्यूल वाहनों पर ध्यान देने की जरूरत

चावल के स्टॉक में से 52 लाख टन इथेनॉल उत्पादन के लिए दिये

नयी दिल्ली, 11 अगस्त. केंद्र में खाद्य एवं जनवितरण प्रणाली विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने सोमवार को कहा कि बदलती भू-राजनैतिक परिस्थितियों में हमें इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के साथ हाइब्रिड और फ्लेक्सी फ्यूल वाहनों पर भी ध्यान देने की जरूरत है.

वाहन निर्माता कंपनियों के संगठन सियाम द्वारा यहाँ जैव-ईंधन दिवस पर यहाँ आयोजित एक कार्यक्रम में चोपड़ा ने कहा कि मौजूदा भू-राजनैतिक परिस्थितियों में ईवी के लिए जरूरी आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है. निकेल, कोबाल्ट, लीथियम, सेमीकंडक्टर चिप ये किसी भी ईवी के मूल आधार हैं. इनकी आपूर्ति श्रृंखला में बाधा के बाद हमें यह सोचना होगा कि हमारे पास क्या विकल्प हैं.

उन्होंने कहा कि सरकार ने ईवी को अब तक काफी प्रोत्साहन दिया है. फेम, उत्पादन आधारित प्रोत्सान और पीएम ई-ड्राइव जैसी योजनायें शुरू की गयी हैं.

उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में हुई प्रगति के बाद सरकार के समक्ष विकल्प स्पष्ट हैं. उन्होंने उम्मीद जतायी कि सरकार उद्योग, ग्राहकों और पर्यावरण समेत सभी पक्षों को ध्यान में रखकर कोई फैसला करेगी.

सचिव ने कहा कि जैव ईंधन के फीड स्टॉक के मामले में कोई समस्या नहीं है. इथेनॉल उत्पादन का करीब 60 प्रतिशत हिस्सा पहले गन्ना से बन रहा था. लेकिन हम पाँच-छह साल पहले की तुलना में काफी मजबूत स्थिति में हैं. राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति में अनाजों से भी इथेनॉल तैयार करने की अनुमति दी गयी है. भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने इस साल बचे हुये चावल के स्टॉक में से 52 लाख टन इथेनॉल उत्पादन के लिए दिये थे.

किसानों को दिये जाने वाले प्रोत्साहन को लगातार बरकरार रहे

भारत में ब्राजील के राजदूत केनेथ फेलिक्स ने कहा कि फीड स्टॉक की प्रचुर उपलब्धता के अलावा ब्राजील में इथेनॉल ब्लेंडिंग की सफल कहानी के पीछे सबसे बड़ा कारक नीति और करों में स्थिरता है. किसानों को दिये जाने प्रोत्साहन को लगातार बरकरार रखा गया है, नीति और अनुसंधान में तालमेल बिठाया गया है. इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कमल किशोर चटीपाल ने कहा कि बायोगैस के लिए फीड स्टॉक की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसका एक जगह संकलन और फिर उसमें से बायोगैस के उपयुक्त अपशिष्ट को अलग करना चुनौती है. देश में 50 करोड़ टन कृषि अपशिष्ट हर साल उत्पन्न होता है जिससे छह करोड़ टन बायोगैस के उत्पादन की संभावना है.

ट्रंप की चेतावनी के बावजूद क्रूड ऑयल सस्ता

भारत-चीन जैसे बड़े खरीदार रूस से तेल खरीदना जारी रख सकते हैं

नई दिल्ली, 11 अगस्त. अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत को दी गई सख्त चेतावनी के बावजूद अंतरराष्ट्रीय क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट जारी है. बाजार का रुख दर्शाता है कि वैश्विक सप्लाई पर फिलहाल कोई संकट नहीं है और भारत-चीन जैसे बड़े खरीदार रूस से तेल खरीदना जारी रख सकते हैं.

6 अगस्त को ट्रंप ने कहा था कि अगर भारत रूस से तेल आयात जारी रखता है, तो 28 अगस्त से भारत से आने वाले सामान पर 25त्न अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा. इससे कई उत्पादों पर टैक्स 50त्न तक जा सकता है. हालांकि, ट्रंप के पिछले फैसलों में यू-टर्न की प्रवृत्ति को देखते हुए निवेशक फिलहाल ज्यादा चिंतित नहीं हैं. सोमवार को ब्रेंट क्रूड 65.81 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जो दो महीनों का सबसे निचला स्तर है. कीमतें दिखाती हैं कि बाजार मानकर चल रहा है कि भारत रूस से तेल लेना बंद नहीं करेगा या जरूरत पड़ने पर अन्य सप्लायर से आपूर्ति पक्की कर लेगा.

भारत का आयात और आगे की तस्वीर

2025 की पहली छमाही में भारत ने औसतन 18 लाख बैरल प्रतिदिन रूसी तेल खरीदा, जो कुल जरूरत का 37 प्रतिशत है. यह ज्यादातर ह्लह्वह्म्ह्य ग्रेड है, जिसे भारतीय रिफाइनर आसानी से प्रोसेस कर लेते हैं. विकल्प के रूप में सऊदी अरब का अरब लाईट या इराक का बसरा लाईट लिया जा सकता है, लेकिन लागत और तकनीकी बदलाव चुनौती हैं. तेल मार्केट में टेको शब्द मजाक में चल रहा है, मतलब ट्रंप अक्सर आखिरी वक्त पर पीछे हट जाते हैं. फिर भी, अगर भारत ने खरीद घटाई और चीन ने उसे बढ़ा दिया, तो वैश्विक तेल राजनीति नया मोड़ ले सकती है.

तकनीकी समस्या के कारण विमान चेन्नई में उतरा

तकनीकी समस्या के संदेह और मार्ग में मौसम की परिस्थितियों के कारण

इस विमान में कई सांसद और अन्य यात्री थे उपस्थित

नयी दिल्ली, 11 अगस्त.केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम् से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के एक विमान को तकनीकी समस्या के संदेह के कारण रविवार रात चेन्नई में उतारना पड़ा. एयर इंडिया ने एक बयान में कहा कि उड़ान संख्या एआई2455 को तकनीकी समस्या के संदेह और मार्ग में मौसम की परिस्थितियों के कारण डायवर्ट कर चेन्नई में उतारा गया. विमान चेन्नई में सुरक्षित उतरा जहां उसकी आवश्यक जांच की जायेगी.

कथित तौर पर इस विमान में कई सांसद भी सवार थे. कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने इस हवाई सफर को अत्यंत डरावना बताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस यात्रा में वे वह त्रासदी के बेहद करीब पहुंच गए थे.

उन्होंने लिखा, उड़ान पहले से ही विलंब से रवाना हुई थी. एयर इंडिया के इस विमान में कई सांसद और अन्य यात्री थे. उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद हमें अभूतपूर्व स्थिति का सामना करना पड़ा. लगभग एक घंटे बाद कैप्टन ने उड़ान सिग्नल में खराबी की घोषणा की और विमान को चेन्नई की ओर मोड़ दिया. लगभग दो घंटे तक हम उतरने की अनुमति का इंतज़ार करते हुए हवाई अड्डे के चक्कर लगाते रहे.

विमान के लैंड करने के पहले प्रयास में दिल दहला देने वाली बात सामने आयी कि उसी रनवे पर एक और विमान था.

वेणुगोपाल ने लिखा कि यात्रियों की सुरक्षा भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती इसलिए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) और नागरिक उड्डयन मंत्रालय से घटना की जाँच करने, जवाबदेही तय करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि ऐसी चूक दोबारा न हो.

स्कोडा ऑटो इंडिया ने मनाई अपनी 25वीं वर्षगांठ

नयी दिल्ली, 11 अगस्त. स्कोडा ऑटो इंडिया ने सोमवार को अपनी 25वीं वर्षगाँठ पर भारत में सबसे ज्यादा बिक्री वाले तीन मॉडलों के सीमित संस्करण पेश करने की घोषणा की है. कंपनी ने बताया कि सीमित संस्करण में कुशाक, स्लेविया और कायलाक मॉडलों को और ज्यादा बेहतर डिजाइन तथा प्रीमियम फीचरों के साथ उतारा गया है. इन वाहनों पर 25वीं वर्षगाँठ का विशेष बैज भी होगा.

स्कोडा ऑटो इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर आशीष गुप्ता ने कहा कि ये विशेष संस्करण कंपनी के प्रशंसकों को ध्यान में रखते हुये पेश किये गये हैं. इनमें स्पोर्टी लुक और प्रीमियम फीचरों को जोड़ा गया है. सीमित संस्करण में तीनों कारों की 500-500 इकाइयाँ उपलब्ध होंगी.

जियो-फाइनेंस ऐप पर 24 रु. में होगी फाइलिंग

टैक्स एक्सपर्ट की सहायता से टैक्स फाइलिंग 999 रु से शुरु

ऐप पर रिफंड ट्रैकिंग और टैक्स नोटिस अलर्ट भी मिलेंगे

मुंबई, 11 अगस्त, 2025. भारत में करदाताओं के लिए टैक्स फाइलिंग और वित्तिय प्लानिंग अब बेहद आसान होने वाली है. जियो-फाइनेंस ऐप ने टैक्स फाइलिंग और टैक्स प्रबंधन के फ़ीचर से लैस एक मॉड्यूल लॉन्च किया है.

मात्र 24 रु कीमत से शुरू होने वाले ये मॉड्यूल्स जियोफाइनेंस ऐप पर ग्राहकों के लिए उपलब्ध हैं. जियो-फाइनेंस ने यह नया फ़ीचर 'टैक्सबडी' के साथ साझेदारी में विकसित किया है. 'टैक्सबडी' ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग और सलाहकार सेवा के लिए जाना जाता है.

इस मॉड्यूल में दो मुख्य फ़ीचर शामिल हैं - टैक्स प्लानर और टैक्स फाइलिंग. टैक्स फाइलिंग सुविधा पुरानी और नई कर-व्यवस्थाओं के बीच भ्रम को दूर करने के लिए डिज़ाइन की गई है, यह ग्राहकों को 80ष्ट और 80ष्ठ जैसी धाराओं के तहत टैक्स का हिसाब किताब करके और टैक्स बचाने में मदद करती है. इसका इस्तेमाल काफी सरल व किफ़ायती है, यह महंगे बिचौलियों पर निर्भरता को खत्म करता है.

दूसरा फीचर है - टैक्स प्लानर, जो भविष्य की टैक्स देनदारियों का अनुमान लगाने और उन्हें कम करने में मदद करता है. माड्यूल के तहत यूजर टैक्स फाइलिंग के लिए, या तो स्वयं रिटर्न दाखिल करने या विशेषज्ञ-सहायता प्राप्त फाइलिंग का विकल्प चुन सकता है.

एयर इंडिया ने शुरू की बोइंग 787 विमानों की रेट्रोफिटिंग

विमान हादसे के बाद 40 करोड़ डॉलर के निवेश

` 27 नैरोबॉडी ए320निओ विमानों की रिट्रोफिटिंग शुरू की गयी

नयी दिल्ली, 11 अगस्त. टाटा समूह की विमान सेवा कंपनी एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमानों की रेट्रोफिटिंग शुरू हो गयी है. कंपनी ने बताया कि 26 बी 787-8 विमानों की रेट्रोफिटिंग (विमान में नये उपकरण या कलपुर्जे आदि जोड़ने का काम) की उसकी योजना है. इसके लिए पहला विमान जुलाई में अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित बोइंग के केंद्र में गया था और अब उसकी रेट्रोफिटिंग शुरू हो गयी है. इसी उद्देश्य के लिए अक्तूबर में एक और विमान कैलिफोर्निया जायेगा और दोनों के दिसंबर तक वापस परिचालन के लिए आने की उम्मीद है.

उल्लेखनीय है कि एयर इंडिया ने इस साल जून में अहमदाबाद विमान हादसे के बाद 40 करोड़ डॉलर के निवेश से अपने बेड़े के लिए रेट्रोफिट कार्यक्रम की घोषणा की थी. सबसे पहले 27 नैरोबॉडी ए320निओ विमानों की रिट्रोफिटिंग शुरू की गयी थी जिसके इस साल सितंबर में पूरी होने की उम्मीद है.

एयरलाइंस ने साल 2027 के मध्य तक 26 वाइड बॉडी बी787-8 विमानों की रेट्रोफिटिंग का काम पूरा करने की योजना बनायी है. इसमें विमान के केबिन की संरचना में बदलाव होने हैं.

आईसीआईसीआई बैंक ने बचत खातों की राशि पांच गुना बढ़ाई

नई दिल्ली,11 अगस्त. आईसीआईसीआई बैंक ने 1 अगस्त 225 या उसके बाद खोले गए नए बचत खातों के लिए मासिक न्यूनतम औसत बैलेंस (एमएबी) की आवश्यकता को 1` रुपये से बढ़ाकर 5` रुपये कर दिया है.

यह बदलाव केवल महानगरीय और शहरी ग्राहकों पर लागू होगा, जबकि पुराने खातों के लिए पुरानी सीमा ही जारी रहेगी. यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक न्यूनतम बैलेंस की अनिवार्यता को पूरी तरह खत्म कर चुके हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सोमवार को कहा कि न्यूनतम शेष राशि तय करना बैंकों का अधिकार है और यह आरबीआई के नियामकीय दायरे में नहीं आता.

भारत-श्रीलंका तटरक्षक बल की उच्च स्तरीय बैठक

समुद्री सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण और खोज-बचाव में सहयोग पर जोर

नई दिल्ली, 11 अगस्त. भारतीय तटरक्षक बल और श्रीलंका तटरक्षक बल के बीच आठवीं उच्च-स्तरीय बैठक सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित की गई. यह बैठक दोनों मित्र देशों के बीच मजबूत और स्थायी समुद्री साझेदारी में एक और महत्वपूर्ण कदम है.

भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व महानिदेशक परमेश शिवमणि ने किया, जबकि श्रीलंका के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रियर एडमिरल वाई.आर. सेरासिंघे ने किया. यह बैठक 2018 में दोनों बलों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत हुई, जिसका उद्देश्य पेशेवर बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देना है.

बैठक में समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया, समुद्री खोज और बचाव, और समुद्री कानून प्रवर्तन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई. दोनों पक्षों ने क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता पहल को मजबूत करने पर भी जोर दिया. दोनों देशों ने साझा समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा, संरक्षा और पर्यावरणीय प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई. इस बैठक में परिचालन समन्वय को गहरा करने, सर्वोत्तम तरीकों को साझा करने और सतत सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय समुद्री स्थिरता को बढ़ावा देने पर भी सहमति बनी.

समाचार विशेष

पंचायत चुनाव में होगी 'पाठशाला' की परीक्षा

भाजपा और सपा के बीच घमासान

लखनऊ. त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए बिछ रही बिसात पर परिषदीय पाठशालों के विलय का मुद्दा तेजी से उभर रहा है. विकास होने, न होने की दुहाई और जातीण गुणा-भाग के साथ शिक्षा से जुड़े इस बिंदु को भी साधने में सभी राजनीतिक पार्टियां जुट गई है. भाजपा और सपा के बीच सबसे ज्यादा घमासान मचा है.

सरकार के फैसले और विरोधियों के गढ़े गए नैरेटिव के कारण गांव-गांव इस पर बहस छिड़ी है. विलय की नीति का सबसे ज्यादा असर भी उन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों में है, जहां पंचायत चुनावों की जीत-हार का पूरा तानाबाना बुना जाना है. ऐसे में भाजपा पूरी ताकत के साथ अपने शिक्षा सुधार के एजेंडे से जनता जोड़ने के जतन कर रही है, जबकि सपा अपनी पीडीए पाठशालाओं के सहारे अपनी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक (पीडीए) की रणनीति को मजबूत करने की कोशिश में है. 'तेरी पाठशाला' बनाम 'मेरी पाठशाला' का विमर्श दोनो पार्टियां खड़ा कर रही है. ऐसे में चुनावों में 'पाठशाला' इस मुद्दे के प्रभाव की भी परीक्षा होना तय है.

प्रदेश में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव और उससे पहले अगले वर्ष अप्रैल-मई में पंचायत चुनाव होने हैं. ऐसे में पंचायत चुनाव को ताकत परखने का अवसर माना जा रहा है और हर राजनीतिक दल इसकी तैयारी में जुटा है. इस सबके बीच सरकार ने कम छात्र संख्या वाले परिषदीय स्कूलों के विलय का निर्णय किया तो विरोधियों ने इसे भाजपा के विरोध बड़ा मुद्दा बना लिया. इस फैसले से दस हजार से अधिक स्कूलों के प्रभावित होने की संभावना है.

गरमा रहा शिक्षा सुधार का मुद्दा

भाजपा अपने फैसले को शिक्षा सुधार का बड़ा कदम बताने के साथ सपा के शासनकाल में शिक्षा की बदहाली का मुद्दा उठा रही है. पढ़ाई के नाम पर राजनीति करने के आरोप लगाकर भी सपा पर हमला बोला जा रहा है. इसके साथ ही विरोध को बेअसर करने के लिए कई बार नीति को स्पष्ट किया जा चुका है. 50 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को नजदीकी विद्यालयों में विलय करने से शिक्षा की सुविधाएं बेहतर होने की बात कही जा रही है और बंद होने वाले विद्यालयों में बाल वाटिकाएं संचालित करने का भरोसा भी दिलाया गया है.

मुंबई निकाय चुनाव में विधानसभा जैसी टक्कर

भाजपा ने सेट किया टारगेट

मुंबई. मुंबई में इस साल होने वाले निकाय चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. सत्तारूढ़ बीजेपी और उसके सहयोगी, अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, तैयारियों में जुटे हैं, जबकि विपक्षी दल कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की एनसीपी और शिवसेना भी अपनी खोई जमीन वापस पाने और मतदाताओं से जुड़ने की कोशिश में हैं.

बीजेपी ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कैडर निर्माण और लगातार नेताओं को शामिल करने पर ध्यान दिया है. हाल ही में, पार्टी ने वसई, अमरावती, रायगढ़ और धाराशिव जैसे क्षेत्रों से 50 से अधिक नेताओं को शामिल किया, जिनमें से कई कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना से आए हैं. बीजेपी ने नवंबर 2024 के विधानसभा चुनाव में 288 सीटों में से 132 पर जीत हासिल की थी, जो लोकसभा चुनाव में उसके खराब प्रदर्शन (28 में से केवल 9 सीटें) के बाद बड़ी उपलब्धि थी.

शिवसेना मुश्किल दौर से गुजर रही

दूसरी ओर, उद्धव ठाकरे की शिवसेना मुश्किल दौर से गुजर रही है. 2019 में 56 सीटें जीतने वाली पार्टी 2024 के विधानसभा चुनाव में केवल 20 सीटों पर सिमट गई. इसके बाद कई वरिष्ठ नेताओं ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए, जिससे उद्धव पर दबाव बढ़ा है. सत्तारूढ़ गठबंधन की 'ऑपरेशन टाइगर' रणनीति ने उनकी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की है.

विशेष | **विपक्षी दलों की जीती सीटों पर निगाह; बनाई जा रही है नई रणनीति**

भाजपा का मिशन-2029 पर फोकस

चंडीगढ़. हरियाणा में भाजपा की निगाह उन विधानसभा सीटों पर है, जहां विपक्षी दलों के विधायक चुनकर आए हैं. राज्य की 9 सदस्यीय विधानसभा में 42 सीटें ऐसी हैं, जिन पर विपक्षी दलों के विधायकों ने चुनाव जीता, जबकि 48 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल कर रखी है.

भाजपा की रणनीति उन विपक्षी विधायकों की विधानसभा सीटों को गोद लेने की है, जहां वह चुनाव हार गई थी. इसके पीछे हारे हुए विधानसभा क्षेत्रों को साल 2029 में होने वाले चुनाव के लिए फिर से मजबूत करने की सोच काम कर रही है.

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल के सहयोगियों और भाजपा विधायकों को सभी 42 सीटों पर काम करने का टास्क सौंपा जाएगा, जिसकी रूपरेखा मंगलवार को होने वाली भाजपा विधायक दल की बैठक में तैयार होगी. सत्तारूढ़ दल के मंत्रियों और विधायकों में छह मंत्री और विधायक ऐसे होंगे, जिन्हें विपक्षी दलों की सीटों पर काम करने की जिम्मेदारी से मुक्त रखा जाएगा. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास चूंकि पूरे राज्य का कार्यभार है, इसलिए उन्हें अतिरिक्त काम करने के लिए लाडवा के अलावा दूसरी कोई विधानसभा सीट नहीं मिलेगी. मुख्यमंत्री पूरे राज्य के प्रवास पर निकलने वाले हैं. भाजपा की सोच है कि मुख्यमंत्री पूरे राज्य के हैं, इसलिए उन्हें अतिरिक्त सीट पर काम करने की जिम्मेदारी से अलग रखा जाएगा.

विधायकों व मंत्रियों से कहा जाएगा कि वे भाजपा के हारे हुए उम्मीदवारों, जिला प्रभारियों व जिला प्रधानों के साथ-साथ संबंधित विधानसभा के प्रमुख नेताओं व कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलें, ताकि उन्हें यह लगे कि भले ही संबंधित विधानसभा से विपक्ष का विधायक चुनकर आया है, लेकिन यहां के लोगों की हरियाणा की सत्ता में पूरी हिस्सेदारी है. भाजपा विधायक दल की सीएम निवास पर होने वाली बैठक में विपक्षी दलों की सीटों के बंटवारे पर चर्चा होगी.

42 सीटों पर फोकस

भाजपा की सोच है कि इस बार भी यदि आरंभ से ही हारी हुई 42 सीटों पर फोकस कर लिया जाए तो 2029 के चुनाव में विपक्षी दलों के सामने कड़ी चुनौती पेश की जा सकती है. इन 42 सीटों में चार सीटें ऐसी हैं, जहां के विधायक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ मंच साझा कर चुके हैं और सार्वजनिक प्लेटफार्म पर उनके कामकाज की सराहना कर चुके हैं. इसके अलावा कई विधायक ऐसे भी हैं, जो सामने आकर मुख्यमंत्री के कामकाज की तारीफ नहीं करना चाहते, लेकिन आंतरिक रूप से वे सरकार के कामकाज से खुश हैं.

कौन होगा बिहार का चुनाव प्रभारी?

पटना. बिहार विधानसभा के चुनाव में अब तीन महीने का समय रह गया है. सितंबर के अंत में या अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनाव की घोषणा होगी. इस लिहाज से चुनाव की घोषणा में दो महीने से कम समय है और अभी तक भाजपा ने बिहार के चुनाव प्रभारी की घोषणा नहीं की है. आमतौर पर चुनाव प्रभारी की घोषणा बहुत पहले हो जाती है. झारखंड विधानसभा चुनाव से कई महीने पहले शिवराज सिंह चौहान और हिमंत बिस्वा सरमा को वहां का चुनाव प्रभारी घोषित किया गया था. ऐसे ही धर्मेंद्र प्रधान हरियाणा के और भूपेंद्र यादव महाराष्ट्र के चुनाव प्रभारी बनाए गए थे.

कार्यालय नगरपालिका परिषद वारासिवनी, जिला - बालाघाट (म.प्र.)

क्रमांक/1985/लो.नि.वि./न.पा.प./2025, // **निविदा आमंत्रण सूचना** // वारासिवनी, दिनांक 06/08/2025

एतद् निम्नलिखित कार्य / सामग्री हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में समस्त पंजीकृत फर्मो / सप्लायरों एवं शासकीय विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से जिनकी अपनी स्वयं की संबंधिते फर्म हो या निमार्ता हो अथवा जो केन्द्र सरकार अथवा म.प्र. सरकार का अद्यतन रूप से बिक्री कर एवं आय कर भुगतान करते हों, से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का विवरण https://mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है।

निविदा विवरण निम्नानुसार है :-

क्रं.	टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
01	02	03	04	05	06
1.	क्र. 2025_UAD_442748_1 दिनांक : 07/08/2025	Supply of Chhayadar, Faldar, Aushadhi Tree (Height 10 to 12 Feet Minimum)	समयावधि : 01 माह लागत : 5,00,000/-	नि.प्र.मूल्य : 2,000/- EMD : 5,000/-	22/08/2025

नोट : - निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://mptenders.gov.in की वेबसाईट पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद, वारासिवनी